Shri Morarka: Is it a fact that at some ports, the unloading facilities not being there, the unloading is delayed, and consequently, some of the ships have been converted into floating godowns for cargo?

Shri Raj Bahadur: That was the complaint initially and that was really the problem. But we have made improvements in the situation, as will be evident from the figures which I shall give. These are comparative figures as on 5th May, 1960 and 15th January, 1962. The figures which I am giving are in tons per day; these are the averages over a fortnight. In the case of Madras, originally it was 426 tons, but now it is 1253 tons. In the case of Tuticorin, it was 719 tons previously and now it is 918 tons. In the case of Cochin, it was 488 tons before, and now it is 726 tons. In the case of Bombay, it was 989 tons before, and now it is 1382 tons. I have figures for the other ports also, but I have given figures only for the important ones.

River Boards

*169. **Shri D. N. Tiwary:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Boards are proposed to be set up for various rivers (inter-State) for regulation of supplies of water;

(b) whether the State Governments concerned have been sounded; and

(c) if so, their reactions?

The Minister of Irrigation and Power (Hafiz Mohammad Ibrahim): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The State Governments concerned with the Mahi, the Mahanadi, the Narmada and the Tapti River Basins have communicated their concurrence while it is awaited from the States concerned with the remaining river basins.

श्री डा० न० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि शुरू शुरू में कितने ऐसे रिवर बोर्डस स्थापित होंगे ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : शुरू तो किया गया है। इन दरियाओं के जिन के कि नाम लिये गये हैं जैसे महानदी, ताप्ती वगैरह दरियाओं के लिये बोर्डस पहले बनाये जायेंगे और उस के बाद और स्टेट्स के लिये बनाये जायेंगे।

श्री डा० न० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि स्टेट्स गवर्नमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से होगा ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : इस में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन का हिसाब नहीं है . . .

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब अगर मुझे जवाब दें तो दूसरे सदस्य भी उन को सुन सकेंगे।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम: मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो रिवर बोर्डस ऐक्ट है उस में उस का एक खास कास्टीट्यूशन दिया गया है। उस के मुताबिक बनते हैं। उस में सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरों का सवाल पैदा नहीं होता . . . .

(Interruptions)

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि महानदी, नर्मदा और ताप्ती के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है तो क्या मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जहां तक नर्मदा का सम्बन्ध है उस के विषय में बहुत वर्षों से . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और मिनिस्टर साहब इस तरह से सवाल कर रहे और जवाब दे रहे हैं मानो एक दूसरे से बात कर रहे हों। अगर माननीय सदस्य मुझ से सवाल करें और मंत्री महोदय मुझे जवाब दें तो तमाम हाउस उन को सुन सकेगा।

डा० गोविन्द दास : मैं यह कह रहा था कि मंत्री जी का जो उत्तर हुआ उस में यह कहा गया कि महानदी, ताप्ती और नर्मदा के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । मैं यह जानना चाहता था कि जहां तक नर्मदा का सम्बन्ध है यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है तो क्या इस विषय में आगे कुछ और प्रगति हुई है ? उस सम्बन्ध में अभी क्या स्थिति है और उस के बारे कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : पोजीशन यह है कि इन दरियाओं का जिनका कि मैं ने नाम लिया है, यह और इन के अलावा और दरियाओं के बाबत उन स्टेट्स को जिनमें कि वह बहते हैं हमारी तरफ से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिखा गया कि रिवर बोर्डस कायम किये जायें । उनके जवाबात हमारे पास आये भी हैं जिनमें बाज में इत्तिफाक है तो बाज में नाइत्तिफाकी भी है । लेकिन जहां तक इन दरियाओं का ताल्लुक है जिनका कि सवाल में जिक्र है उनके मुताल्लिक मैं ने अर्ज किया कि उनके लिये यह काम किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : उनका सवाल नर्मदा के निस्बत यह था कि उसके मुताल्लिक पहले से कोई तरक्की और हुई है ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अभी तरक्की का सवाल उस में उठता नहीं है । यह पहला कदम है जो रिवर बोर्ड बनाने के लिये उठाया गया है यानी स्टेट्स से कम्युनिकेशन करने का है ।

Shri U. M. Trivedi: On a point of order.

इस सदन की भाषा या तो अंग्रेजी है या हिन्दी है लेकिन जवाबात जो दिये जा रहे हैं वह उर्दू में दिये जा रहे हैं । "इत्तिफाक" वगैरह उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है । मंत्री महोदय की भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही है . . .

डा० राम सुभग सिंह : वह हिन्दी है ।

Shri S. M. Banerjee: There is no point of order (*Interruptions*).

Mr. Speaker: There ought not to be any controversy raised so far as this is concerned, so long as we can quite well understand what is spoken. This matter was raised once before. When Shri Purshotamdas Tandon was here and when the late Maulana Azad was answering a question put by an hon. Member, he raised this question and I remember the Maulana's historic reply. The question asked by Shri Tandon was, 'What is the language in which the answer is being given? In reply, it was said that it was Hindi. It is all Hindi that we can understand and, therefore, there ought not to be any controversy on this score.

Shri Hari Vishnu Kamath: Will the function of these proposed Boards be advisory only or will they be armed with adequate powers to ensure that riverine disputes between States of the Indian Union do not assume menacing proportions detrimental to national unity and harmony and become almost as intractable as disputes between sovereign States like India and Pakistan?

Hafiz Mohammad Ibrahim: These Boards will perform all the functions which are assigned to them under section 30 of the River Boards Act. They are given there.

Shri Hari Vishnu Kamath: This is hardly an answer.

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य मुझे इजाजत दें, तो मैं इस का जवाब दे सकता हूं कि उन को तसल्ली रखनी चाहिये कि इस झगड़े को ऐसी प्रोपोर्शन में कभी नहीं होने दिया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : तसल्ली तो हो गई ।